

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुरपीठासीन अधिकारी :-अनीता मीना, आर.ए.एस.प्रकरण संख्या 3 / 2020(बांसवाड़ाआर्डर)

1. भरत कुमार पुत्र श्री जबरिया, जाति बंजारा, निवासी लाम्बापाडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा(राज.)
2. मणीलाल पुत्र श्री जबरिया, जाति बंजारा, निवासी लाम्बापाडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती रूपाली पत्नी स्वर्गीय जबरिया, जाति बंजारा, निवासी लाम्बापाडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

कलजी पुत्र श्री लखमा, जाति बंजारा, निवासी लाम्बापाडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम-1955 विरुद्ध

निर्णयउपखण्डअधिकारी घाटोल

दिनांक06.10.2020,प्र.सं.31 / 19

----/----

- उपस्थित(वक्तबहस)
1. श्री जयेन्द्र पुरोहितअभिभाषकअपीलान्तगण
  2. श्री भालचन्द नागर अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

----::----

निर्णयदिनांक 27-06-2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्तगण द्वाराएक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी नंबर 303 रकबा 0.07 ग्राम लाम्बापाडा में स्थित है, जिसमें विपक्षी का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी प्रार्थीगण से झगड़ा-फसाद करते हैं, जिससे उनके विरुद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज करवायी गयी है, फिर भी विपक्षी प्रार्थीगण की भूमि में जबरन प्रवेश



करते हैं एवं उनके उपयोग-उपभोग में बाधार उत्पन्न करते हैं एवं गाली-गलौज करते हैं। अतः विपक्षी को मूलवाद निस्तारण तक इस आ आ की जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त भूमि में जबरन प्रवेश नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करें एवं प्रार्थीगण के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को सुनने के बाद प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जानेके आधार पर अपने निर्णय दिनांक 06-10-2020 से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05-11-2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तलब करने पर रेस्पोंडेन्ट की ओर से वकील श्री भालचन्द नागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अपीलान्त विवादित आराजियात का रेकार्डेड खातेदार है, जिसकी पुष्टि जमाबन्दी संवत् 2075-2078 से होती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त रेकार्डेड खातेदार होने से विपक्षी/रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षी प्रार्थीगण की विवादित आराजी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं एवं गाली-गलौज करते हैं, जिसकी एफ.आई.आर. भी अपीलान्त द्वारा दर्ज करायी गयी है एवं अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष साबित कराया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं मानकर खारिज कर दिया, जो त्रुटि है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोंडेन्टगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त/प्रार्थीगण को सुनने के बाद प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्तगण ने अधिनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजाके समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि विपक्षी/रेस्पॉन्डेंट द्वारा उनके कब्जे काशत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्त/प्रार्थीगण के कथन मात्र से उनके प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों को साबित नहीं माना जा सकता। अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में एफ.आई.आर. की फोटो प्रति प्रस्तुत की है, किन्तु उसमें किसी प्रकार की आराजी नंबर का उल्लेख नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्त ने जिस आराजी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा चाही है, उक्त एफ.आई.आर. उसी भूमि के संबंध में की गयी है। वैसे भी फौजदारी प्रकरणों के आधार पर अपीलान्त राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्त/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जाने से खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्तसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06-10-2020 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27-06-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर